RAJYA SABHA

Friday, The 3rd March, 1989/12th Phalguna, 1910 (Saka)

The House met at eleven of the clock. **Mr. Chairman** in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shortage of drinking water in Delhi

*141. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that whereas the population of the Capital has increased by 10 lakhs during the last three years the Supply of drinking water has not been increased to that extent;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what steps are being taken to meet the water shortage in the capital and the amount of funds allocated if any, for the purpose?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) and (b) Production of water has increased during the last three years from 377 to 410 million gallons a day.

(c) Schemes for further augmentation of the water supply by 70 million gallons per day are already in hand and are in different stages of implementation. These will be completed by April, 1990. Total outlay in the Seventh Plan of Delhi on water supply scheme is Rs. 136.59 crores.

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Mr. Chairman, Sir, I am very much pained to hear the reply given by the Hon. Minister. It is quite apparent that she has not been able to appreciate or assess the grimness of the situation in its right perspective. Sir, nobody can deny that the chronic water shortage in Delhi adversely affects various colonies every year. In many areas especially in summer the crisis goes from acute to alarming and particularly in April 1987 the situation had become very grim and in some of the colonies people were forced to pay for a barrel of water, i.e., 80 litres of water–prices anywhere between Rs. 6 and Rs. 15, depending on the season and the power position. Sir, this question had been agitated so many times in the Metropolitan Council and in Delhi Corporation as well. I have specifically asked the hon. Minister that whereas the population of the capital has increased by ten lakhs during the last three years, why has the supply of drinking water not been increased to that extent, and she has replied that during the last three years they have improved the supply of water by 33 million gallons a day. Sir, up to December 1988, the shortage of water supply in Delhi, which was 63 million gallons a day, they have improved the position by 33 million gallons a day. This shows the apathy of the Government towards the acute problem which is faced by the people of Delhi. Sir, it is very shameful that we cannot even meet the demand of drinking water in Delhi, in the capital itself. If this is the case here, what shall happen in villages and rural areas? However, Sir, the Hon. Minister has said that there are so many schemes in hand for augmentation of the water supply by 70 million gallons per day and these shall mature only by 1990. Well, Sir, I ask the hon. Minister to give the details of these schemes in hand.

श्रीमती मोहसिना किदवई: सभापति जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले साल पीने के पानी की दिक्कत दिल्ली में हुई थी। इससे पहले इतनी दिक्कत कभी नहीं हुई और यह माननीय सदस्य को अच्छी तरह से मालूम है कि पिछले साल जो पानी की दिक्कत हुई थी उसमें कुछ भगवान का भी हाथ था, खुदा का भी हाथ था। इतनी जबर्दस्त ड्राउट कंडीशंस थीं कि जिसकी वजह से कुछ कालोनियों में पीने के पानी की वाकई दिक्कत हुई और उसके लिए हम सबको सख्त परेशानी थी। मिनिस्ट्री ने पूरी तरह से वार फुटिंग पर काम किया। एम०सी०डी० और डी०डी०ए०, जो भी उससे कन्सर्ड अथारिटीज़ हैं उन्होंने भी पूरी कोशिश की। दिल्ली में जो भी पानी की व्यवस्था है और जहां से हम पानी हासिल करते हैं वह

दो स्टेट हैं, यू०पी० और हरियाणा। मैं यह भी कह सकती हूं कि इन दोनों स्टेट्स ने पिछले ड्राउट के वक्त में दिल्ली के लोगों को पीने के पानी की मदद की। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जितनी हमारी डिमान्ड है दिल्ली में पीने के पानी की वह 482 एम०जी०डी० यानि मिलियन गैलन पर डे है, उसमें से इस वक्त हमारे पास 410 एम०जी०डी० की व्यवस्था है और बाकी जो मैंने कहा कि 70 एम०जी०डी० जो हम बढ़ाने वाले हैं, जो इन-हैंड है हमारे पास, उसकी तफसील मैं बताना चाहूंगी कि वजीराबाद में जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें हम 40 एम०जी०डी० बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पांच रैनी वैल्स हमारी बनाने की प्लानिंग है उसमें 15 एम०जी०डी० की बात है। ओखला प्लांट से 12 एम०जी०डी० और 50 ट्यूबवैल्स के जरिए 3 एम०जी०डी०। इस तरह से टोटल आता है 70 एम०जी०डी०। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए हम थोड़ी-बहुत व्यवस्था पानी की करेंगे और 1989-90 तक हमारी उम्मीद है कि यह वाटर सप्लाई जो दिल्ली में है वह बढ़कर 480 एम०जी०डी० हो जाएगी, अप्रैल 1990 तक।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक: चेयरमैन साहब, जो आनरेबल मिनिस्टर ने जवाब दिया, इसे सुनकर मुझे बड़ी हैरानी है कि मैंने तो 63 मिलियन गैलन पर डे शारटेज बताई और इन्होंने एडमिट किया है कि 72 मिलियन गैलन पर डे है और जो पानी की शार्टेज है, उसका तो जवाब ही नहीं दिया कि शार्टेज है या नहीं?

On the floor of the House she has admitted that there is shortage of water in Delhi at present by 72 million gallons a day. She has described some of the schemes in hand which will mature, as I have already said, by 1990, and they shall provide only 70 million gallons a day. But these are only short-term measures. The population of Delhi is swelling very rapidly because of different evils, like the migratory population from the neighbouring States, and the main culprit in this regard is the DDA itself. So many colonies, unauthorised colonies. are coming up in Delhi; so many jhugi and jhompri colonies are there. They have no employment; they are out of work, and the population of Delhi is increasing...

MR. CHAIRMAN: Put your question.

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: With this rapid growth of population it is estimated that Delhi will need at least three times the existing supply of water, to meet the demand by 2001. At least 572 million gallons we need in one and a half years, that is, by 1990 and 702 million by 1995. However, I would like to know from the hon. Minister whether the schemes that she has enumerated, will remain only on paper, and will remain only a dream for the people of Delhi or whether the Government is living in मुंगेरी लाल के हसीन सपने? लोगों को हसीन सपने आप दिखा रहे हैं।I want to know whether these schemes will ever become a reality for the people of Delhi. I would also like to know whether the report of the Tata Consultancy Service Commission of the Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking has concluded that Delhi has reached a saturation point in so far as construction of rainy wells, as she has described, on the Jamuna bed is concerned and whether two of the wells constructed earlier had to be closed down as the water had an iron content therein.

श्रीमती मोहसिना किदवई: सभापति जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि मैं इन हसीन सपनों की दुनिया में नहीं रहती, मैं तो हकीकत की दुनिया में रहती हूं और इसलिए हकीकत का बयान करती हूं।

श्री सभापति: हसीन सपनों की दुनिया को उन पर छोड़ दीजिए... **(व्यवधान)**

श्रीमती मोहसिना किदवई: मैंने पहले ही ऐडमिट किया है जितना पानी मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया, लेकिन प्यास से या पानी के बिना खुदा न खास्ता किसी के मरने की नौबत नहीं आई। इस समय दिल्ली में पर हैड 50 गैलन पानी की जरूरत है और इस हिसाब से हम पानी की व्यवस्था कर रहे है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, झुग्गी झोंपड़ी के लोगों के लिए भी पानी की व्यवस्था की जाती है। चाहे वह घरों में रहें या झुग्गियों में, पानी की हर शख्स को जरूरत है। मैं कह सकती हूं कि कोई झुग्गी ऐसी नहीं है जहां पानी की व्यवस्था न की गई हो। पर बदकिस्मती से जो बड़ी बीमारी पिछले साल फैली, उसकी वजह से लोगों को पानी पहुंचाने में और ज्यादा जल्दी हमने की है और

जहां खराब पानी पहुंच रहा था वहां अच्छा पानी पहुंचाने की कोशिश की। 60 हज़ार से ज्यादा कनेक्शन पानी के हमने दिए हैं। जहां कनेक्शन नहीं दिए जा सकते हैं वहां टैंकरों से हम पानी दे रहे हैं। इसलिए पानी की आने वाले दिनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस साल भी बरसात हुई है और हमें उम्मीद है कि पानी की आने वाले दिनों में दिक्कत नहीं होगी। यह तो शार्ट टर्म पालिसी की बात है जो मैंने आपको बताई।

जहां तक लांग टर्म पालिसीज का सवाल है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि टैहरी डैम जो यू०पी० में बनने वाला था वह 1995 तक पूरा होगा। उससे 300 क्यूसिक पानी मिलने की योजना है। कसाऊ डैम जो यू०पी० में बनने वाला है उससे 0.5 एम०ए०एफ० पानी मिलने की आशा है। इसी तरह से रेणुका डैम जो हिमाचल प्रदेश में बनने वाला है उससे 0.4 एम०ए०एफ० पानी दिल्ली को दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। ये हमारी लांग टर्म पालिसी है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस परेशानी पर काबू पाया जा सकेगा।

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: What about the second part of my question about the Tata Consultancy Service Commission? They have arrived at some conclusions.

श्रीमती मोहसिना किदवई: श्रीमन्, ये कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं। अभी तक रेनी वैल्स की जो बात की जा रही थी दिल्ली में उसका परिणाम यह भी हुआ है कि कहीं-कहीं पानी पीने के लायक पाया गया है और कहीं-कहीं ब्रेकिश वाटर है तो हमें ऐसे वैल्स बंद करने पड़ते हैं क्योंकि उस पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। जितने वेनी वैल्स बने, एक मयूर विहार में बनाया गया है। यदि उनमें कोई दिक्कत आएगी तो उसको हम देखेंगे। इस वक्त किसी अन्य जगहों की पानी की समस्या के बारे में मुझे पता नहीं है।

PROF. C. LAKSHMANNA: Sir, listening to the Minister's replies to supplementaries, I take it that she wants to live in reality and she does not want to live in golden dreams. But unfortunately, this Government has reduced most of the people in this country to such a state that they can only live in golden dreams and not in reality. That is the tragedy of it. Having stated that...

श्री सभापति: ड्रीम्स तो अच्छे होते हैं। सभी एम०पी० दिल्ली में रहते हैं ख्वाब देखते हैं।

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: He is speaking for Andhra.

PROF. C. LAKSHMANNA: I am not speaking for Andhra. I am speaking about Delhi and Delhi alone. (*Interruptions*) Therefore there is no point for the Minister to bring in Andhra Pradesh here. There are enough places where Andhra Pradesh can be debated and discussed.

MR. CHAIRMAN: Please don't bring in Andhra Pradesh.

PROF. C. LAKSHMANNA: I am not bringing in Andhra Pradesh, but if I do not go on record, I will be doing injustice to Andhra Pradesh.

Having stated that, the Minister has already stated that for 8 million population, which is the recorded population of Delhi today, 40 gallons per person is available. As per the norms that are available, about 100 gallons per person is required to live a good, reasonable life with water. But, unfortunately, that has not been planned at all.

Having stated that, I want to bring to the notice of the Minister that there will be five more five star hotels coming up in the city of Delhi. According to the norms of five star hotels, huge amounts of water will be taken by the five star hotels. As it is, there are a large number of five star hotels, with the result that 70 million gallons, which she hopes to have by April, 1990, will not be able to meet the requirements of the population. Therefore, I would like to know, since the Minister is very much interested to be on the ground and realistic, what will be the realistic estimates and actual provision of water facilities for the people of Delhi and Delhi alone because of the increasing population, migration of population and also the policy which has been adopted

by this Government in allowing five more five star hotels in Delhi? I would like to know what the position is.

श्रीमती मोहसिना किदवई: सभापति महोदय, अलग-अलग फाइव स्टार होटल पर कितना खर्चा होगा आज के दिन कुछ नहीं कहा जा सकता। यह जो 70 मिलियन गैलन की बात है यह दूसरे परपज के लिए है। जितनी दिल्ली की पापुलेशन है और आगे जितनी आने वाली है उसी के लिए इंतजाम किया जा रहा है। दो हजार ए०डी० में जो हमारी डिमांड होगी उसके मुताबिक यह लांग टर्म और शोर्ट टर्म पालिसीज हैं। मैं समझती हूं पानी की इतनी जबर्दस्त शार्टेज नहीं है कि सारे काम बंद कर दें। इस वक्त फाइव स्टार होटलों को बनाना बंद कर देंगे तो टूरिज्म मिनिस्टरी भी खत्म हो जायेगी।

PROF. C. LAKSHMANNA: I never said that. In only ask if this has been taken into consideration in programming for water.

श्रीमती मोहसिना किदवई: इसमें तो सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं। सारी चीजें उसके परव्यू में आती हैं। जहां तक पानी के इस्तेमाल की बात है सब मिला कर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसमें इंडस्ट्रीज की भी नीड्ज हैं, डुमेस्टिक भी हैं और दूसरी नीड्स भी हैं।

श्री सभापति: श्री भंडारे। आपको बार-बार हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। जब आप आ जाते हैं तब ही हमें पता लग जाता है।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: When I am sitting behind Ministers, nobody notices me.

Sir, this is a very acute and chronic problem. But I want to dispute the figures which have been given by the hon. Minister. Her estimate about availability is 410 MGs, whereas the requirements are 480 MGs per day. Delhi is the capital of the country. It has a large migratory population and over 2½ lakh people visit it every day either for site-seeing or for conferences and other purposes. According to very modest estimates...

MR. CHAIRMAN: And for Parliament session also.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: ...the requirement today is 600 million gallons per day. Therefore, I say that there is forgetfulness also. But I do not want her to forget. The reality is that these 482 million gallons per day, whichever has been given by the Department, is an entirely erroneous figure. Now, the resources are limited, the water here is brackish, as has been admitted just now.

MR. CHAIRMAN: At some places.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: At some places.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Though we are on the banks of the Jamuna, the Jamuna does not have enough supply for Delhi. The real supply would come from Ravi, Beas and Sutlej and the requirement from that source is 0.871 m.a.f. as against which we are getting only 0.2 m.a.f. This is what we were to get out of the Ravi-Beas Tribunal. Rajasthan was a party, Punjab was a party, Haryana was a party, and they all fought for agricultural use of the water whereas drinking use of water takes precedence over all other uses of water. So, I want to know from the honourable Minister as to what steps are being taken to see that this deficit between 0.2 m.a.f. and 0.871 m.a.f. from the Ravi, Beas and Sutlej source is met, because Delhi is left high and dry.

श्रीमती मोहसिना किदवई: सभापति जी, जो रावी कमीशन बना था उसके सामने दिल्ली ने अपना केस रखा था, लेकिन बद्किस्मती से उसमें दिल्ली को हिस्सा नहीं मिला। मैं भी माननीय सदस्य से सहमत हूं कि दिल्ली में जमुना बह रही है और कुछ तो दिल्ली के लोगों को पानी मिलता है, दो सौ क्वीजिक। तीन सौ क्वीजिक मिलता है।

श्री सभापति: क्या आप अब कुछ कर सकती हैं?

श्रीमती मोहसिना किदवई: अब क्या करें। सिवाय इसके कि जो नये डेम्स बन रहे हैं उनसे मिले। दूसरी

बात मुझे यह कहनी है कि दिल्ली का जो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसको भी इफेक्टिव बनाने की बात है। उसके लिए एक कंसलटेंट की मदद ली गई थी और उन्होंने प्रोग्राम भी बनाकर दिया है। उस पर भी अमल कर रहे हैं ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अभी दिक्कत यह है कि किसी कालोनी में ज्यादा पानी मिलता है और कहीं कम मिलता है। उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लिकेज होती है उसके लिए हमने नये इक्वीपमेंट लिये हैं और इंजीनियर्स को ट्रेन्ड भी किया है ताकि वे जो हिडन लिकेज होती है उसको भी वे निकाल सकें और जो वेस्टेज होती है उसको भी कम किया जा सके।

श्री वीर भद्र प्रताप सिंह: ये जो 50-60 जन-साधारण के इस्तेमाल की टोटियां टूटी रहती हैं और उनसे पानी बहता रहता है, पानी जाया जाता है ... **(व्यवधान)**

श्री सभापति: उन्होंने कहा है कि उसके लिए कोशिश कर रहे हैं।

श्री वीर भद्र प्रताप सिंह: श्रीमन्, मैं, चाहता हूं कि आप अनुसंधान करवायें और ऐसी टोटियां लगवायें जो आसानी से न टूटें और चुराई भी न जा सकें। इसके अलावा जो एक लाख कनेक्शन्स कुछ लोगों ने और अधिकारियों ने मिलकर ले लिये हैं जिनके लिए पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं वे खुले पड़े रहते हैं। आपके जो मैन हैं वे भी 50-60 साल पुराने हैं, उनसे सीपेज होती रहती है, मिलावट होती है, उनमें भी सुधार लाने की जरूरत है। चौथा और आखिरी क्षेत्र यह है कि बिल्डिंग बनवानी हो तो पानी की कमी नहीं है, लौन्स के लिए पानी की कमी नहीं है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में आप कानून को सख्ती से इंफोर्स क्यों नहीं करते हैं? उनके लिए आप ट्यूबवैल और हैण्ड पाइप क्यों नहीं बनाते हैं और पानी क्यों नहीं बचाते हैं? आप उत्तर प्रदेश से पानी मत खींचिये।

श्रीमती मोहसिना किदवई: सभापति जी, जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, इसमें हम विचार ही नहीं कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। जो 10 एम०सी०डी० डी०डी०ए० और सी०पी०डब्ल्यू०डी० इस्तेमाल करते हैं उसको भी हमें बंद करना पड़ेगा और उनको ट्यूबवैल और दूसरे जरियों से सिंचाई के लिये पानी देना पड़ेगा जो वे पार्क्स और लौन्स को मेंटेन करने के लिए लेते है। आपने यह भी सुना होगा, दिल्ली के जो चीफ एक्जीक्यूटिव कौंसिलर हैं श्री जगप्रवेश चन्द्र जी, उन्होंने खास किस्म की टोटियां लगाने के लिए विज्ञापन भी दिया है और उसके लिए इनाम भी दिया है ताकि अच्छे किस्म के नल और टोटियां लगाई जा सकें और पानी का वेस्टेज न हो। मैं एक बात यह भी कहना चाहती हूं कि इसमें एजूकेशन की बात भी है। हम उसके तरफ ध्यान दे रहे हैं और टी०वी० और मिडिया से उसका प्रचार भी कर रहे हैं।

SHRI NARREDDY THULASI REDDY: It is said that the leakage of drinking water to the extent of 37 per cent, use of treated water for gardening in VIP bungalows, excessive supply of water to the extent of 150 gallons per day per person in some areas, especially in South Delhi and colonisation of various areas by the Delhi Development Authority without consulting the Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking are the main reasons for the drinking water crisis in Delhi. If so, what are the steps taken in this matter?

Further, Sir, the Chairman of the Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking recently said that the Government had assured supply of 150 MGD from the Tehri Dam and 460 MGD from the Kesar Dam being built on the Toni river in U.P. What progress has been done in this proposal?

श्रीमती मोहसिना किदवई: इसके लिये तो मुझे नोटिस चाहिये होगा कि क्या प्रपोजल्स हैं।

MR. CHAIRMAN: This question does not relate to her Ministry. It relates to the Ministry of Water Resources.

*142. [*Transferred to the 8th March, 1989.*]

*143. [*The questioners (Dr. R. K. Poddar and Shri Mostafa Bin Quasem) were absent. For answers* vide *col. 30-31* infra.]